दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

जीरों में अनुष्का के अभिनय की कायल...... P-8

वर्ष : 14 ▸ अंक : 6 ▸ गाजियाबाद, नवंबर, 2018 ▸ मूल्य : 4 रुपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

पीएफ खातेदारों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, घर खरीदने के लिए मिलेगा लोन, ईएमआई

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

गाजियाबाद। अब जल्द ही आपका अपना घर होने का सपना पूरा हो सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने करोड़ों अंशधारकों को घर खरीदने के लिए लोन और ईएमआई की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि केंद्र सरकार इस स्कीम को पूरे देश में लागू कर दे।

दिसंबर में पेश होगा प्रस्ताव

ईपीएफओ ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत वो जल्द ही देश के प्रमुख शहरों में अपनी तरफ से मकान बनवाएगा। यह प्रस्ताव दिसंबर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में पेश किया जाएगा। श्रम मंत्रालय की तरफ से पेश किए जाने वाले इस प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लगने के बाद इसे वित्त मंत्रालय में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

इनको मिलेगी लोन, ईएमआई की सुविधा

प्रस्ताव के अनुसार जिन लोगों का पीएफ खाता तीन साल से अधिक समय का है उनको घर खरीदने के लिए आसानी से लोन और ईएमआई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही खाते में जमा 90 फीसदी राशि को निकालने की छूट भी मिलेगी। लोन की राशि पर जो ईएमआई बनेगी उसको भी पीएफ खाते के जरिए चुकाया जा सकेगा।

गिरवी रखनी होगी राशि

ईपीएफओ के केंद्रीय आयुक्त वीपी जॉय ने बताया कि हम ईपीएफओ के उपभोक्ताओं के लिए हाउसिंग स्कीम लाने जा रहे हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी पीएफ राशि गिरवी रखकर घर खरीद सकते हैं और कर्ज का भुगतान ईपीएफ खाते से ईएमआई के जरिये कर सकते हैं।

गारंटर बनेगा ईपीएफओ

इस योजना के तहत ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं के लिए गारंटर बनेगा ताकि वे अपनी सेवा अवधि के दौरान खुद के लिए किफायती घर खरीद सकें। हालांकि अपने उपभोक्ताओं के लिए जमीन खरीदने या मकान बनाने की संगठन की कोई योजना नहीं है। पिछले साल ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने का एजेंडा सीबीटी की बैठक में तय हुआ था। बैठक के दौरान विशेषज्ञ समिति ने उनके लिए घर मुहैया कराने की एक रिपोर्ट भी पेश की थी।

बैंकों से मिलेगा कर्ज

समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश को मंजूर कर लिया कि कर्मचारियों को घर खरीदने की सुविधा मुहैया कराई जाए जहां वे अपने पीएफ संग्रह से अग्रिम राशि ले सकें और इसका भुगतान ईएमआई के रूप में कर सकें। कर्मचारी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से यह कर्ज ले सकते हैं। कर्मचारियों को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

ऑटो चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरुक किया

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

गाजियाबाद। यातायात माह के चलते यातायात पुलिस की ओर से गुरुवार सुबह मोहन नगर चौराहे पर ऑटो चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरुक किया गया। इस दौरान उन्हें ऑटो चलने के लिए दिशा–निर्देश भी दिए गए। टीएसआई ओंकार सिंह सहरावत ने बताया यातायात माह के चलते वाहन चाल. कों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए जागरुक किया जा रहा है। मोहननगर चौराहे पर ऑटो चालकों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। साथी ऑटो चालकों को इनका पालन करने की हिदायत भी दी गई। उन्होंने बताया कि ऑटो चालकों को लाइसेंस साथ रखने, ऑटो पर अपना निजी मोबाइल नंबर अंकित करने, वर्दी पहनकर ऑटो चलाने, परमिट के अनुसार ही ऑटो का संचालन करने, म्यूजिक सिस्टम तेज आवाज में नहीं चलाने और निर्धारित सवारियां बैठाने की हिदायद दी गई।

ईपीएफओ दे सकता है बड़ी सौगात

तीन साल नौकरी करने पर होगा बीस लाख का फायदा

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

गाजियाबाद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को जल्द ही अपने अंशधारकों को एक बड़ी सौगात दे सकता है। इसके तहत ग्रैच्युटी के लिए समय सीमा घटाना और पेंशन में इजाफा करना शामिल हैं।

तीन साल हो सकती है ग्रैच्युटी की सीमा

फिलहाल एक संस्थान में लगातार 5 साल काम करने पर पीएफ अंशधारकों को ग्रैच्युटी मिलती है। अब ईपीएफओ इस समय सीमा को घटाकर के तीन साल करने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अब अंशधारकों को 20 लाख रुपये ग्रैच्युटी के तौर पर मिलते हैं। इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की संभावना है। मिनिमन पेंशन 2000 रुपये करने का बैठक में निर्णय होने की उम्मीद भी है। वित्त मंत्रालय न्यूनतम पेंशन पर अपनी मंजूरी दे चुका है।

फिक्सड टर्म वालों को भी मिलेगा लाभ

अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारी को भी ग्रैच्युटी का फायदा मिल सकता है। यह वो कर्मचारी होते हैं, जिन्हें अनुबंध पर दो साल से अधिक समय के लिए रखा जाता है। ऐसे कर्मचारियों को नौकरी करने के समय के अनुपात में ग्रैच्युटी मिलने को हरी झंडी मिल सकती है। पीएफ के तर्ज पर ग्रैच्युटी के लिए यूएएन जैसा खाता खोला जा सकता है।

4 दिसंबर को होगी बैठक

ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की आगामी चार दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें इन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय ने तैयार किए हैं। केवल इन प्रस्तावों को बैठक में पास कराना है। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद यह सौगात करोड़ों अंशधारकों को मिल जाएगी।

बजट को लेकर एक और परम्परा तोड़ने की तैयारी में मोदी सरकार!

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में भी चीजें अपने ही अलग ढंग से कर सकती है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि सरकार पुराने रिवाजों को तोड़ते हुए 2019 में पूरा बजट पेश करेगी, जबकि इसके पहले लोकसभा चुनावों की स्थिति होने पर सरकारें अंतरिम बजट पेश करती रही हैं। अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि हम निरंतरता बरकरार रखेंगे। हम सिर्फ चुनाव के चलते अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जहां कहीं भी खर्च में अंतर होगा, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 2018–19 का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी,जो कि आमतौर पर अगली सरकार का काम होता है।

सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान के नेतृत्व में एक पैनल का गठन भी किया है। ये पैनल वित्त मंत्रालय में अगले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का चयन करेगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि विभागों को 2018–19 के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट्स और 2019–20 के बजट एस्टीमेट्स के लिए पहले ही खत भेजे जा चुके हैं।साथ ही उद्योगों और अन्य स्टेक होल्डर्स से चर्चा भी की जा रही है कि

ताकि बजट को लेकर उनकी क्या अपेक्षा है इसका पता लगाया जा सके।

वित्तमंत्री अरुण जेटली का लगातार छठा बजट

वित्त मंत्रालय ने एक पत्र भेजकर मंत्रालयों से कहा है कि 'कृपया 30 नवंबर 2018 तक अपने विभाग से संबंधित जरूरी सूचना या सुझाव उपलब्ध कराएं।' 2019–20 के बजट भाषण में शामिल करने के लिए सामग्री भेजने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर से ही 2019–20 के बजट की तैयारी शुरू कर दी थी। बजट 1 फरवरी 2019 को पेश किया जाएगा। ये बजट वित्तमंत्री अरुण जेटली का लगातार छठा बजट होगा। निर्धारित व्यवस्था के तहत चुनाव वर्ष में लेखानुदान पेश किया जाता है और नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है।

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8374.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

अब पेटीएम से भर सकेंगे एलआईसी का प्रीमियम भी, दोनों के बीच हुई साझेदारी

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। मोबाइल वॉलेट पेटीएम से अब तक आप ने मोबाइल रिचार्ज किया होगा. पैसे ट्रांसफर किए होंगे. अब आप इसके जरिए अपनी एलआईसी पॉलिसी का प्रीमध्यिम भी भर सकते हैं.

पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने इस खातिर एलआईसी के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत ग्राहक अब एलआईसी बीमा प्रीमियम का भुगतान एक मिनट से भी कम समय में पेटीएम द्वारा कर सकेंगे. वन97 के मुताबिक पेटीएम पर 30 से भी ज्यादा बीमा कंपनियों का प्रीमध्यिम आसानी से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है.

इन कंपनियों में एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशध्यिल लाइफ, रिलायंस लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, टाटा एआईए के अलावा अन्य शामिल हैं. पेटीएम के सीओओ किरण वासीरेड्डी ने कहा, "हमारे देश में बीमा प्रीमियम का भुगतान ज्यादातर कैश में ही होता है.

हम चाहते हैं कि पेटीएम के जरिये लोगों को बिना किसी दिक्कत के आसान भुगतान का अनुभव मिले. इसी खातिर एलआईसी और अन्य अग्रणी बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है.

सर्विस चार्ज को कर्मचारियों में नहीं बांटा तो देना होगा इनकम टैक्स

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। अब होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ग्राहकों की ओर से मिले सर्विस चार्ज को अपने कर्मचारियों में बांटना होगा नहीं तो वह कर योग्य माना जाएगा। दरअसल, आयकर विभाग को शिकायत मिली है कि होटल और रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज के रूप में मिले रुपये को या तो अपने कर्मचारियों में बांटते नहीं हैं और अगर बांटते हैं तो बहुत कम मात्रा में देते हैं। आयकर विभाग ने अपने फील्ड ऑफिसर से कहा है कि वह होटल और रेस्टोरेंट के बही खाते की जांच करें कि क्या वे सर्विस चार्ज के रूप में मिले रुपये को अपने कर्मचारियों में बांट रहें हैं या नहीं। विभाग ने यह भी कहा है कि अधिकारी यह भी पता लगाएं कि रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को सर्विस चार्ज पूरा दे रहे हैं या आधा बांट रहे हैं। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर वेटर को सर्विस चार्ज का पैसा नहीं दिया गया, तो होटल मालिक इसे अपनी आमदनी में शामिल करें।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS & PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT Social & Technical Audit

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- Payroll
- TDS
- ESI Act
- EPF Act
- Minimum Wages Act
- Bonus Act
- Payment of Gratuity Act
- Standing Order
- Workmen Health & Safety Policy
- First Aid Training & Certificates
- Factory Plan & Site Plan
- Factory Act-1948
- Shop & Establishment Act
- Social & Technical Audit

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818697406 / 9818036460

H.O. : BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad U.P.-201002. INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794
Mobile : 9818697406

B.O. : The Ithum IT Park, Suite #007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India

E-mail ID : - legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, नवंबर, 2018

आधार बनवाने को नहीं लगेगी लाइन, अलग कक्ष बनेगा

उद्योग विहार (नवंबर–2018)
गाजियाबाद। सुविधा एक–नवयुग मार्केट के मुख्य डाक घर में आधार कार्ड बनवाने के लिए आते हैं लोग–दिसंबर तक कक्ष तैयार हो जाएगा, इसी हफ्ते काम होगा शुरूगाजियाबाद। संवाददाताडाक विभाग में जल्द ही आधार कार्ड बनवाने की वेटिंग कम होगी।

नवुयग मार्केट के मुख्य डाकरघर में आधार कार्ड के लिए अलग से एक कक्ष बनाया जा रहा है। साथ ही दो और काउंटर बनाए जा रहे है। इससे आधार कार्ड बनाने के काम में तेजी आएगी। आधार कार्ड बनवाने की भीड़ देखते हुए डाक घर के अधिकरियों ने ये फैसला लिया है। विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि डाकघर में आवेदकों को एक–एक महीने से अधिक की वेटिंग मिल रही है।

आलम यह है कि एक दिन में कुल 25 से 30 आधार कार्ड ही बन पाते हैं। इसकी वजह से आवेदकों को समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी मुश्किल डाक विभाग के स्टाफ के लोगों की भी आ रही है। बता दें कि आधार कार्ड बनवाने की अच्छी–खासी भीड़ विभाग पहुंचती है।

जबकि डाक विभाग में संबंधित कार्यों के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसकी वजह से कई बार परिसर में पैर तक रखने की जगह नहीं होती है। आवेदकों को अधूरे कार्य के साथ डाकघर से वापस लौटना पड़ता है। वर्तमान में विभाग के अन्य काउंटर के साथ ही आधार कार्ड बनवाने की खिड़की बनाई गई है।

मगर अब आधार कार्ड कार्यालय को डाक विभाग के पीछे हॉल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही कंप्यूटर और अन्य सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि एक दिन में अधिक से अधिक आवेदकों के कार्ड तैयार हो सकें।

वरिष्ठ पोस्टमास्टर गुलशन नागपाल ने बताया कि जल्द से जल्द आधार कार्ड सेंटर को शिफ्ट किया जाएगा। जिससे दोनों जगह का काम आसानी से हो सके। और आवेदकों को सबसे अधिक लाभ मिल सके।

राजनगर एक्सटेंशन फ्लाईओवर की एक लेन जनवरी से चालू होगी

- अगले साल मार्च में पूरा होगा दूसरी लेन का निर्माण
- फ्लाईओवर शुरू होने से वाहन चालकों को लाभ मिलेगा

उद्योग विहार (नवंबर–2018)
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर एक हिस्सा जनवरी से यातायात के लिए चालू हो जाएगा। अगले साल मार्च तक दूसरी लेन का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इससे हजारों वाहन चालकों को लाभ मिलेगा। जीडीए के मुख्य अभियंता वीएन सिंह ने बताया कि एक्सटेंशन चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर पर जनवरी से गाजियाबाद से मेरठ की ओर जाने वाली लेन पर ट्रैफिक संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे मेरठ की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी। चौराहे से रोजाना औसतन 80 से 90 हजार वाहन गुजरते हैं। फ्लाईओवर की एक लेन शुरू होने से करीब 50 हजार वाहनों को सुविधा मिलेगी। जीडीए 65 करोड़ खर्च कर फ्लाईओवर का निर्माण करा रहा है। दूसरी लेन का काम मार्च में पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में इस चौराहे पर लालबत्ती को हटा कर यातायात के लिए दो यू–टर्न बनाए हैं। इस फ्लाईओवर को दो भागों में बनाया जा रहा है। पुल की दोनों लेन के बीच 18 मीटर की दूरी है, क्योंकि मेरठ रोड की सेंट्रल वर्ज पर रैपिड रेल प्रस्तावित है। इसलिए उसके ट्रैक के लिए बीच में यह जगह छोड़ी गई है। जिससे बीच में से रैपिड रेल ट्रैक गुजर सके।

सीटी स्कैन का काम दूसरी कंपनी को सौंपा

उद्योग विहार (नवंबर–2018)
गाजियाबाद। संजयनगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा को मरीजों के लिए शुरू करने की जिम्मेदारी अब कृष्णा कंपनी को दे दी गई है। बुधवार को जनपद के संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण कर इसे जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। संयुक्त निदेशक ने बुधवार को मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और संयुक्त जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भारत योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं संयुक्त जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। संयुक्त जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से सीटी स्कैन मशीन लगकर तैयार है। इसके अलावा सीटी स्कैन कक्ष भी तैयार है लेकिन जिस कंपनी को इसे शुरू करना है,वह नहीं आ रही है। ऐसे में अब दूसरी कंपनी कृष्णा को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। यह कंपनी जनवरी तक इस सुविधा को शुरू कर देगी। जनवरी के पहले सप्ताह से सीटी स्कैन जांच शुरू होने की पूरी उम्मीद है। जितनी जल्दी यह सुविधा शुरू होगी,उतनी ही जल्दी एमएमजी अस्पताल जाने से इस क्षेत्र के मरीजों को राहत मिलेगी। इसके अलावा जनपद के संयुक्त निदेशक से आयुष्मान योजना को चलाने के लिए अन्य स्टाफ की मांग की गई है।

बुलंदशहर और अलीगढ़ डाकघर में खुलेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र

उद्योग विहार (नवंबर–2018)
गाजियाबाद। बुलंदशहर और अलीगढ़ डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। योजना के तहत जल्द ही इन केंद्रों से सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की योजना शुरू की है। इस योजना में गाजियाबाद क्षेत्र में आने वाले जिलों के डाकघरों में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक मेरठ, वृंदावन और आगरा में खोले जा चुके हैं। अब जल्द ही बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी खोले जाएंगे। पासपोर्ट दफ्तर गाजियाबाद की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। अलीगढ़ में 28 तो बुलंदशहर के डाकघर में 29 नवंबर को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की शुरुआत होगी।

> ***बुलंदशहर और अलीगढ़ के डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इनकी तिथि तय कर दी गई है। इसके बाद संबंधित जिलों के व्यक्ति वहीं पर एप्वाइंटमेंट ले सकते हैं।***
> ***–सुब्रतो हाजरा, पासपोर्ट अधिकारी गाजियाबाद***

लोगों को यह मिलेगा लाभ

अभी तक गाजियाबाद क्षेत्र के जिलों के आवेदकों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समय लेने के बाद गाजियाबाद में साक्षात्कार के लिए आना होता था, लेकिन डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बाद इन लोगों को गाजियाबाद आने की आवश्यकता नहीं होगी। इन आवेदकों को दिए गए केंद्रों में अप्वाइंटमेंट मिल जाएगा। इसके बाद पासपोर्ट बनकर उनके घर पहुंच जाएगा। हालांकि इन पासपोर्ट सेवा केंद्रों में तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा नहीं होगी। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन के बाद गाजियाबाद में ही अप्वाइंटमेंट लेना होगा।

गाजियाबाद क्षेत्र आने वाले जिले

गाजियाबाद क्षेत्र में सहरानपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर जिला आता है।

संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक, चयन प्रक्रिया पर नए सिरे से मंथन

उद्योग विहार (नवंबर–2018)
दिल्ली। प्रदेश के संस्कृत कालेजों में गुपचुप तरीके से चल रही अनियमित नियुक्तियों पर रोक लग गई है। शासन ने प्रदेश के कई जिलों से मिलने वाली शिकायतों को देखते यह निर्देश दिया है। संबंधित जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। यह भी निर्देश हैं कि कालेजों के प्रबंधक जिला विद्यालय निरीक्षकों से अनुमति लेकर ऐसा कर रहे हैं, प्रक्रिया शासन के निर्देशों के विपरीत है। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों और माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों का पारदर्शी तरीके से चयन करने के निर्देश हैं। माध्यमिक कालेजों के निर्देश हो चुके हैं, जबकि महाविद्यालयों की चयन प्रक्रिया को लेकर मंथन जारी है।

शिक्षकों की अनियमित तरीके से नियुक्तियां

प्रयागराज, फैजाबाद और आजमगढ़ मंडलों के जिलों में महाविद्यालय व माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की अनियमित तरीके से नियुक्तियां की गई। शासन में टीकरमाफी संस्कृत विद्यालय सुलतानपुर, दयाराम संस्कृत पाठशाला चंद्रेश्वर आजमगढ़ और प्रतापगढ़ जिले के माध्यमिक व महाविद्यालयों में अनियमित तरीके से नियुक्तियों की लिखित शिकायत पहुंची। संयुक्त सचिव जयशंकर दुबे ने तीनों मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे अनियमित नियुक्तियों की कार्यवाही तत्काल रोक दें। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट भी मांगी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश हुए हैं कि संस्कृत कालेजों में अनियमित नियुक्तियां न होने पाएं।

वेतन भुगतान की जांच कर रिपोर्ट भेजें

मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने अपने जिलों के डीआइओएस को निर्देश दिया कि पिछले दो वर्ष में की गई नवनियुक्ति व वेतन भुगतान की जांच करके रिपोर्ट भेजें। इसमें नियुक्तियों का विज्ञापन, प्रशासन योजना, पद सृजन की प्रमाणित प्रति, रिक्ति का कारण, अनुमा. `दन की प्रति और भुगतान आदेश की प्रति भी मांगी गई। यह भी निर्देश हुआ कि कुछ जिलों में डीआइओएस से कालेज प्रबंधकों ने अनुज्ञा लेकर नियुक्तियां की हैं, यह प्रक्रिया शासन के निर्देशों के प्रतिकूल है। इस आदेश से खलबली मची है।

चयन बोर्ड को जिम्मा, चयन ठप

प्रदेश सरकार ने संस्कृत माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों का चयन का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र को सौंपा है। इसके लिए निर्देश हुए कि अब चयन से पहले उनकी लिखित परीक्षा होगी। यह भी निर्देश हुआ कि जरूरी हो तो नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव दिया जाए। आदेश होने के बाद से अब तक चयन बोर्ड ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है। इसीलिए कालेज संचालकों को अनियमित नियुक्ति का मौका मिल रहा है।

छोटे वाहनों के लिए नहीं कोई डायवर्जन

उद्योग विहार (नवंबर–2018)
गाजियाबाद। गढ़ कार्तिक मेले के कारण हापुड़ रोड पर केवल भारी वाहनों के लिए डायवर्जन किया गया है। छोटे वाहन सामान्य रूप से हापड़ की ओर जा सकते हैं। वहीं लालकुआं से बुलंदशहर रोड पर वाहनों के लिए कोई मार्ग परीवर्तन नहीं है। गाजियाबाद में केवल ईस्टर्न पेरीफरल एक्सप्रेस–वे से ही भारी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

Editorial

04

P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, नवंबर, 2018

सम्पादकीय

जोखिम और हिम्मत

सत्येन्द्र सिंह

राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक बसों में रोजाना का सफर आसान बनाने और खासकर महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम करने के तमाम वादों और दावों की हकीकत क्या है, इसका उदाहरण मंगलवार को हुई एक शर्मनाक घटना के रूप में एक बार फिर सामने आया। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में एक क्लस्टर बस में महिला सीट पर बैठी एक युवती के पास खड़े युवक ने बेहद अश्लील हरकत की और आपत्ति जताने पर आक्रामक भी हो गया। लेकिन युवती ने पूरी बहादुरी से उसका मुकाबला किया, उसकी पिटाई की और बस रुकवा कर आखिर उसे पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में महिलाओं को रोज जिस जोखिम और परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसमें यह घटना किसी को सामान्य महत्त्व की लग सकती है। पर यह घटना समूचे सामाजिक रवैये को आईने के सामने रखती और बताती है कि आधुनिकता और विकास के दावों के बीच हमारा समाज किस तरह की कुंठाओं और हीनताओं से ग्रस्त होता गया है। आखिर भरी बस में उस व्यक्ति के भीतर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह न केवल उस युवती के पास खड़ा होकर अपनी हरकतों से उसे असहज करने लगा, बल्कि आपत्ति जताने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा? विडंबना यह है कि जब उस युवती ने आवाज उठाई तो बस में मौजूद करीब पचास यात्रियों में से किसी ने उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं समझी। यहां तक कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी चुप रहे, जबकि उस महिला की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है। बस में कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। सिर्फ एक युवक ने लड़की का साथ दिया और आरोपी को पुलिस के आने तक पकड़े रखा। इस समूची घटना में युवती की बहादुरी तारीफ के काबिल है। उसने इस आशंका के बावजूद यह हिम्मत दिखाई कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले कई बार बेहद हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं और अपने बचाव में जानलेवा हमला कर देते हैं। पर सच यह है कि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का मनोबल इसीलिए बढ़ता है कि उनके खौफ के सामने कोई आवाज नहीं उठाता। जाहिर है, यह सामाजिक रवैये की विडंबना है। सवाल है कि जो सरकारें हर कुछ दिन पर दिल्ली में घर से बाहर कहीं भी आने-जाने के लिए महिलाओं के सफर को सुरक्षित और सहज बनाने का आश्वासन देती रहती हैं, उन्होंने क्या ऐसे इंतजाम किए हैं कि सार्वजनिक बसों में महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डीटीसी और क्लस्टर बसों की तादाद अब भी जरूरत के मुकाबले इतनी कम है कि अक्सर काफी अंतराल के बाद आने वाली बसों में लोग भरे रहते हैं और व्यस्त समय में तो इधर-उधर होने की भी गुंजाइश मुश्किल से निकलती है। ऐसे में ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है, जिन्हें बसों में सवार होने से लेकर उसमें मौजूद कुंठित और आपराधिक मानसिकता वाले पुरुषों की गलत हरकतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर महिलाएं कई तरह की मजबूरियों के बीच चुप रह जाती हैं, लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाती भी है, तो उसे बाकी यात्रियों का साथ नहीं मिल पाता। सरकार और पुलिस-तंत्र की नाकामी के समांतर सवाल है कि यह किस तरह का समाज बन रहा है, जिसमें भरी बस में भी अपराधियों को ऐसी हरकत करने में हिचक नहीं हो रही और उसे ऐसा करते हुए आसपास खड़े तमाम लोग तमाशबीन रहते हैं?

नोटा का प्रयोग कर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं आप?

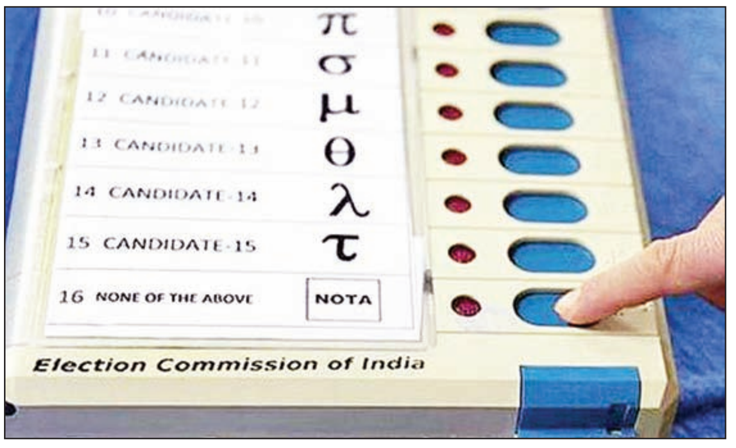

नोटा के प्रयोग को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों खासतौर से चर्चा हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य स्थानों पर चुनाव प्रचार का कार्य अब पूरे जोर पर है वहीं केन्द्र व राज्य सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करने और किसी भी दल या उम्मीदवार को नकारते हुए नोटा के प्रयोग को लेकर सामाजिक संगठनों या तात्कालिक प्रतिक्रियावादियों द्वारा आवाज उठाई जा रही है। हालांकि गुजरात व कर्नाटक सहित अन्य प्रदेशों में पिछले दिनों हुए मतदान के दौरान कुछ प्रत्याशियों की जीत तो नोटा वोटों के लगभग बराबर या आसपास वाली स्थिति रही है। पर नोटा का प्रयोग कर आखिर हम संदेश क्या देना चाहते हैं ? नोटा के प्रयोग से जुड़ा इससे भी बड़ा यक्ष प्रश्न यह उभरता है कि नोटा का प्रयोग कर हम प्राप्त क्या कर लेंगे ? हालांकि नोटा के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों से नाइत्तफाकी या यों कहें कि नाराजगी व्यक्त करने के रूप में देखा जाता है पर इससे नोटा का प्रयोग करने वाले मतदाताओं को हासिल कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि देखा जाए तो यह अपने मत देने के अधिकार को खड्डे में डालने जैसा है। नागरिकों या दूसरे शब्दों में कहें तो गैरसरकारी संगठनों की मांग पर चुनाव आयोग ने आम मतदाताओं को पिछले चुनावों से नोटा के प्रयोग की सुविधा भी दे दी है। नोटा यानी चुनावों में खड़े हुए उम्मीदवारों में से भी कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रति अविश्वास होना या राजनीतिक दलों के प्रति विरोध जाहिर करना है पर यह समस्या का समाधान ना होकर देखा जाए तो जिम्मेदार मतदाताओं का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार ही माना जाएगा। सोचने की बात है कि कुछ मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग कर भी लिया तो इसका परिणाम यह तो होने वाला नहीं है कि उस क्षेत्र से कोई विजयी नहीं होगा या यह भी नहीं हो सकता कि सरकार ना बने। ऐसे में नोटा के प्रयोग से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। नोटा के प्रयोग की जगह अपनी बात कहने का अन्य विकल्प भी खोजा जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो यह साफ हो जाना चाहिए कि सरकार चुनने का अधिकार हमें पांच साल में एक बार मिलता है। अब सरकार चुनने के अधिकार को भी हम नोटा प्रयोग के नासमझी भरे निर्णय से एक तरह से खो देते हैं। हमारे देश की चुनाव व्यवस्था का सारी दुनिया लोहा मानती है। हालांकि पिछले सालों से हारने वाले राजनीतिक दल कुछ संगठनों को आगे कर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाने लगते हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाकर जनादेश को चुनौती देने लगते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने खुली चुनौती देकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को सिरे से खारिज कर दिया है। अब यह साफ हो चुका है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में अधिक शांतिपूर्ण व निष्पक्षता से चुनाव होने लगे हैं। हालांकि हारने वाले दल ही प्रक्रिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोआ सहित पांच राज्यों में हुए चुनावों के बाद विपक्षी दलों ने हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर डालने का प्रयास करते हुए चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने इसे खुली चुनौती के रूप में लेते हुए ईवीएम से छेड़छाड़ सिद्ध करने की जिस तरह से चुनौती दी उससे सभी दल बगले झांकने लगे। हारने वाला दल ईवीएम को दोष देने लगता है जिसे उचित नहीं माना जा सकता। अभी पिछले दिनों ही उदयपुर में चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर अब कोई प्रश्न नहीं उभर रहा है। अब तो वीवीपेट का निर्णय भी किया जा चुका है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईवीएम जैसी बेहतरीन सुविधा के बावजूद नोटा के प्रयोग जैसा माहौल बनाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। कुछ स्थानों पर मतदान के बहिष्कार का माहौल भी बनाया जाता है। मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं करने या मतदान का बहिष्कार करने को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी गंभीरता से लिया है। पिछले दिनों ही सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई कि जो मतदान नहीं करते उन्हें सरकार के खिलाफ कुछ कहने या मांगने का भी हक नहीं है। आखिर क्या कारण है कि शतप्रतिशत मतदाता मतदान केन्द्र तक नहीं पहुंच पाते? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और चुनाव आयोग के मतदान के प्रति लगातार चलाए जाने वाले कैम्पेन के बावजूद मतदान का प्रतिशत ज्यादा उत्साहित नहीं माना जा सकता। यह भी सही है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की माकूम व्यवस्था व बाहरी पर्यवेक्षकों के कारण अब धन-बल व बाहु बल में काफी हद तक कमी आई है। ईवीएम और चुनाव आयोग के निरंतर सुधारात्मक प्रयासों का ही परिणाम है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावों में दुरुपयोग के आरोप तो अब नहीं के बराबर ही लगते हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हम बड़े गर्व से दावे कर रहे हैं कि इस बार सर्वाधिक प्रतिशत लोगों ने लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति दी है। मतदान के पुराने सारे रेकार्ड तोड़ दिए हैं। ज्यादा मतदान से इस दल को फायदा होगा या दूसरे दल को। मतदान प्रतिशत से किसको कितना लाभ मिलेगा या हानि होगी इसका विश्लेषण भी होने लगा है। यह विश्लेषण भी होने लगा है कि किस जाति-धर्म व किस आयु वर्ग के लोगों ने कितना मतदान किया है। यह भी विश्लेषण करते नहीं चूक रहे कि महिलाओं का अमुक दल के प्रति झुकाव अधिक है या पुरुषों का अमुक दल के साथ अधिक झुकाव है। टेलीविजन चैनलों पर हम यह विश्लेषण करते भी नहीं थक रहे कि किस दल को कितना मत मिलने जा रहा है। कौन जीत रहा है और कौन-सा दल हार रहा है। किसको कितना मत-प्रतिशत मिल रहा है। यह भी कि किस दल के प्रति मतदान का प्रतिशत कितना स्विंग कर रहा है। चुनाव आयोग के मतदान करने के लिए सघन प्रचार अभियान और सरकारी व गैरसरकारी संस्थानों और मीडिया द्वारा मतदान के लिए प्रेरित करने के बावजूद मतदाताओं की मतदान के प्रति बेरुखी गंभीर चिंता का विषय है। गैरसरकारी संगठनों, सामाजिक मंचों, चैनलों पर लंबी लंबी बहस का हिस्सा लेने वाले बुद्धिजीवियों को मतदाताओं को लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाना चाहिए। मतदान का बहिष्कार या नोटा का प्रयोग आपकी नाराजगी तो दर्शा सकता है पर साथ ही आपके मतदान के अधिकार के प्रति गैरजिम्मेदारी भी साफ कर देता है। आखिर आम मतदाता का भी दायित्व होता है। सरकार चुनने के लिए हमें पांच साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि इस अवसर को भी हम बहिष्कार या नोटा के प्रयोग से खो देते हैं तो इससे अधिक गैरजिम्मेदाराना काम क्या होगा।

आर्सेनिक ग्रस्त क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिकों ने विकसित किया ट्रांसजेनिक चावल

चावल की फसल में आर्सेनिक का संचयन एक गंभीर कृषि समस्या है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब फफूंद के अनुवांशिक गुणों का उपयोग करके चावल की ऐसी ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की है, जिसमें आर्सेनिक संचयन कम होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रजाति के उपयोग से आर्सेनिक के खतरे से निपटने में मदद मिल सकती है। इस अध्ययन के दौरान मिट्टी में पाए जाने वाले वेस्टरडीकेल ऑरेनटिआका नामक कवक में उपस्थित आर्सेनिक मेथिलट्रांसफेरेज (वार्सएम) जीन का क्लोन तैयार करके उसे एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसिएन्स जीवाणु की मदद से चावल के जीनोम में स्थानांतरित किया गया है। एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमेफेसिएन्स मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु है, जिसमें पौधे की अनुवांशिक संरचना को बदलने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यह अध्ययन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के शोधकताओं द्वारा किया गया है। चावल की नयी ट्रांसजेनिक प्रजाति और सामान्य प्रजातियों की तुलना करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन दोनों को आर्सेनिक से उपचारित किया है। शोधकताओं ने पाया कि नयी विकसित ट्रांसजेनिक प्रजाति की जड़ों और तनों में संचित आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से अपेक्षाकृत कम थी। शोधकताओं का कहना है कि चावल की इस ट्रांसजेनिक प्रजाति में अकार्बनिक आर्सेनिक को मेथिलेट करके विभिन्न हानि रहित कार्बनिक पदार्थ, जैसे- वाष्पशील आर्सेनिकल आदि बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। संभवतः इसी कारण न केवल चावल के दानों, बल्कि भूसे और चारे के रूप में उपयोग होने वाली पुआल में भी आर्सेनिक संचयन कम होता है। शोधकताओं की टीम इस ट्रांसजेनिक प्रजाति के नियामक अनुमोदन हेतु इसके खाद्य सुरक्षा परीक्षण और क्षेत्रीय परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, शोधकर्ता चावल में आर्सेनिक चयापचय क्रियाओं का अध्ययन करने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इसके भीतर आर्सेनिक के प्रवेश और चयापचय क्रियाओं को समझा जा सके। इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता डॉ. देवाशीष चक्रवर्ती ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि हमारे अध्ययनों से पौधों, मुख्य रूप से चावल में आर्सेनिक परिवहन प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। इस अध्ययन से प्राप्त परिणामों का उपयोग आणविक प्रजनन, जीन संशोधन या ट्रांसजेनिक तकनीकों द्वारा चावल में आर्सेनिक के संचयन को कम करने के लिए विकसित की जाने वाली विधियों में किया जा सकता है। अब शोधकर्ता चावल में आर्सेनिक संचयन को कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विधियां विकसित करने में जुटे हुए हैं।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
गाजियाबाद / नोएडा

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, नवंबर, 2018

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का होगा विकास: योगी

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

हापुड़। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थस्थलों के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। गढ़ गंगा मेला और अमरोहा जिले में लगने वाले तिगरी मेले के बीच पुल बनाकर आपस में जोड़ने के लिए परियोजना बनाई जाएगी। आस्था का सम्मान करना समाज के साथ प्रदेश व देश के हित में भी होगा। उन्होंने कहा कि गन्ने का बकाया छह हजार करोड़ का भुगतान 30 नवंबर तक होगा।

गढ़मुक्तेश्वर मेला पांच हजार वर्ष पुरानी परंपरा

कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों की समस्या को समझते हुए बताया कि हमारे लिए गन्ना किसानों का बकाया चुनौती थी, लेकिन सरकार ने गन्ना किसानों का 40 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि चार हजार करोड़ का साफ्ट लोन गन्ना मिलों को दिया जा रहा है, लेकिन यह धनराशि गन्ना मिल को नहीं बल्कि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 119 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है, जबकि दो चीनी मिलें नए सत्र में शुरू हो जाएंगी। कहा कि अगर चीनी के दाम बाजार में कम हुए तो भी किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला पांच हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। गढ़ बृजघाट के पर्यटन को लेकर उन्होंने बीस करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें मनोरंजन पार्क, लेजर साउंड शो, श्रद्धालुओं के लिए विश्राम शेड आदि का कार्य कराया जाएगा।

वेस्ट यूपी पर जमकर बोले सीएम

सीएम ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की खेती देश की समृद्धि और पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है। यहां के नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। चाहे बहन बेटियों, किसानों या फिर नौजवानों की सुरक्षा का मामला हो। जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ खास तीर्थ

कृष्ण जन्मभूमि
द्वारिकाधीश मन्दिर
विश्राम घाट
केशी घाट
बांके बिहारी मन्दिर
गोविन्द देव मन्दिर
मदन मोहन मन्दिर
रंगनाथ जी मन्दिर
इस्कॉन मन्दिर
कुसुम सरोवर
मानसी गंगा
राधाकुण्ड
संकेत
हरिदेव जी मन्दिर
दानघाटी
ब्रह्माण्ड घाट
दाऊजी का मन्दिर
प्रेम मन्दिर
पांडव किला
सूरज कुंड
कालीपलटन मंदिर
जैन श्वेतांबर मंदिर
हस्तिनापुर तीर्थ
द्रौपदी की रसोई
हस्तिनापुर अभ्यारण्य
गढ़मुक्तिश्वर महादेव का मंदिर
गंगा मंदिर
मीराबाई की रेती
ब्रज घाट
झारखंडेश्वर महादेव
कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर

प्रशाासन ने भेजी 102 राशन डीलरों की कुंडली

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

गाजियाबाद। जिला आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण घोटाला मामले में फंसे 102 राशन डीलरों की कुंडली शासन को भेजी है। सूत्रों के अनुसार, जिला स्तर पर की गई जांच में सभी 102 राशन डीलरों ने अप्रैल से कितना राशन आवंटित किया और कितने का वितरण किया आदि की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। जिला आपूर्ति विभाग ने यह पूरा डेटा सरकार को भेजा है। बता दें कि राशन घोटाले की शिकायत खाद्य आयुक्त आलोक कुमार को मिली तो उन्होंने इस मामले की जांच की।

जांच में खुलासा हुआ कि कालाबाजारी रोकने के लिए अपनाई गई नई तकनीक में भी आरोपितों ने सेंध लगाई है और आधार नंबर में संशोधन कर दूसरे नंबर फीड किए गए। इसके साथ ही ऑपरेटरों की मदद से सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की गई और इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड जीतू और रोहित ने गौतमबुद्धनगर के दादरी से प्रदेश के 43 जिलों में राशन घोटाले को अंजाम दिया है। इस घोटाले की जांच एसटीएफ कर रही है।

जनवरी से शुरू होगा एलिवेटेड रोड को नोएडा से जोड़ने का काम

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

गाजियाबाद। हिंडन एलिवेटेड रोड को नोएडा (डीएनडी फ्लाइवे) से जोड़ने की कवायद एक और कदम आगे बढ़ी है। सर्वे कंपनी ने जीडीए को डीएनडी तक के लिए 3 विकल्प दिए हैं। जीडीए को इसमें से एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद ही इस प्रॉजेक्ट का एस्टिमेट तैयार करने व टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि नए साल से इस प्रॉजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। अभी सर्वे कंपनी ने जो तीन मार्ग सुझाए हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें टीम चेक करेगी कि किस मार्ग के निर्माण में कम दिक्कत होगी और लागत भी कम आएगी।

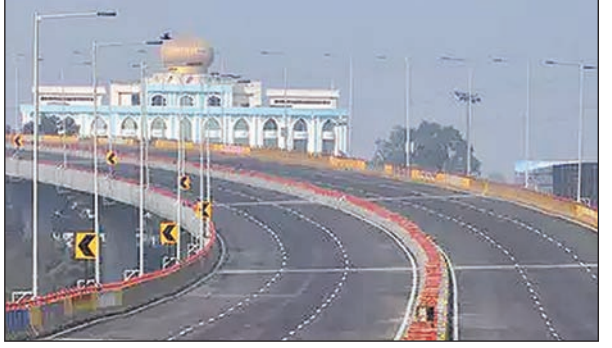

नोएडा व दिल्ली जाना हो जाएगा आसान

हिंडन एलिवेटेड रोड के डीएनडी से लिंक होने के बाद शहर के लोगों के लिए नोएडा के साथ–साथ दिल्ली के कालिंदी कुंज व कालकाजी की तरफ पहुंचना आसान हो जाएगा। अभी पब्लिक को नोएडा और दिल्ली पहुंचने में कहीं न कहीं जाम का सामना करना पड़ता है। इसके बन जाने के बाद यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। फिलहाल जीडीए के अधिकारी प्रॉजेक्ट की फंडिंग को लेकर चिंतित हैं। इसके निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हर रास्ते की जमीन का होगा सर्वे

जीडीए ने सर्वे करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है कि विकल्प के रूप में बताए गए तीनों मार्गों में आने वाली जमीन किस विभाग की है। इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही जीडीए की टीम फाइनल करेगी। क्योंकि जमीन का पता चलने के बाद ही लागत का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। अधिकारी बताते है कि जमीन अधिग्रहण के लिए भुगतान करना पड़ेगा।

ये हैं तीन विकल्प

पहला विकल्प– एनएच–9 व एलिवेटेड रोड के जंक्शन पॉइंट से हिंडन कट कैनाल के समानांतर गाजीपुर कूड़ाघर की ओर स्थित भूमि से होते हुए कोंडली पुल व गाजीपुर नाले के बगल से निकलकर धर्मशाला रोड व न्यू अशो. कनगर मार्ग की क्रॉसिंग से डीएनडी फ्लाईओवर तक। इसकी दूरी 6.9 किमी है।

दूसरा विकल्प– एनएच–9 व एलिवेटेड रोड के जंक्शन पॉइंट से कोंडली पुल से पहले नोएडा स्थित शिवाजी मार्ग होते हुए दल्लूपुरा रोड व अमलताश मार्ग से रजनीगंधा अंडरपास तक। इसकी दूरी 7.94 किमी है।

तीसरा विकल्प– एनएच–9 व एलिवेटेड रोड के जंक्शन पॉइंट से कोंडली पुल से पहले ही नोएडा स्थित शिवाजी मार्ग होते हुए दल्लूपुरा रोड के पहले चौराहे से उद्योग मार्ग होते हुए डीएनडी फ्लाईओवर तक। इसकी दूरी 8.2 किमी है।

क्या कहते हैं अधिकारी

वीएन सिंह, चीफ इंजिनियर, जीडीए का कहना है कि हिंडन एलिवेटेड रोड को नोएडा के साथ जोड़ने के लिए सर्वे कंपनी ने तीन विकल्प सुझाए हैं। हम उसमें से बेहतर विकल्प का अध्ययन कर रहे हैं। लागत, दूरी और बाधा को ध्यान में रखते हुए विकल्प का चयन किया जाएगा।

शहर के ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को लेकर डीएम ने जीडीए को दी टाइमलाइन

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

गाजियाबाद। शहर के ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को लेकर डीएम रितु माहेश्वरी बहुत अधिक गंभीर हैं। जिसके चलते पिछले दिनों जीडीए के चीफ इंजीनियर समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में जीडीए के चीफ इंजीनियर को सीआरआरआई की ट्रैफिक मूवमेंट प्लान के आधार पर तेजी के साथ काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इस प्लान पर अभी स्पीड से काम नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से शहर के अलग–अलग एरिया में जाम की नौबत बनी रहती है। फिलहाल उन्होंने इंदिरापुरम, मोदीनगर और मुरादनगर एरिया के अलावा जीटी रोड के एलिवेटेड रोड के काम को पूरा करने के लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी है। इस टाइमलाइन की वजह से जीडीए के अधिकारी टेंशन में हैं।

जीडीए के अधिकारी बताते हैं कि जो डेडलाइन तय की गई है उस पर काम पूरा किया जाना बहुत मुश्किल है। मालूम हो कि शहर में जाम की समस्या को लेकर आए दिन डीएम के पास शिकायत आ रही थी। इसी कारण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जीडीए के चीफ इंजीनियर वी.एन. सिंह के अलावा कोई नहीं पहुंचा था। जबकि सीआरआरआई समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था। निर्देश दिया गया है कि भविष्य में होने वाली बैठक में जीडीए के चीफ इंजी. नियर को सभी विभागों के अधिकारियों की शामिल करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम ने अपने निर्देश में कहा कि सीआरआरआई की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर अवैध कट को बंद करके सड़क चौड़ीकरण किए जाने का काम किया जाना है। लेकिन वीसी ने कहा कि पहले सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जाए, फिर उसके बाद ही अवैध कट को बंद किया जाए। जबकि जीडीए पहले अवैध कट को बंद कर रहा था फिर चौड़ीकरण का काम। इसकी वजह से वहां जाम की नौबत पैदा हो रही थी। इस काम को 30 नवंबर तक पूरा करने की टाइमलाइन तय की गई है।

मोदीनगर क्षेत्र में सीआरआरआई की रिपोर्ट राज चौपला और झिलमिल पर यूटर्न बनाया जाना है। राज चौपला पर यूटर्न बनाए जाने काम शुरू किया गया है। लेकिन काम की स्पीड तेज नहीं होने से डीएम नाखुश हैं। वह चाहती हैं कि यहां पर 30 नवंबर तक यूटर्न बनाए जाने का काम पूरा किया जाए। साथ ही झिलमिल चौराहे पर यूटर्न बनाए जाने का काम 31 दिसंबर तक पूरा किए जाने की टाइम लाइन तय किया गया है।

डीएम ने स्पष्ट किया है कि घंटाघर भाटिया मोड़ तक एलिवेटेड रोड बनाया जाना जरूरी है। डीएम ने चीफ इंजी. नियर को निर्देश दिया है कि टेंडर समेत अन्य औपचारिकता को पूरा करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाए।

मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर

एयरटेल और वोडाफोन बंद करने जा रही हैं फ्री इनकमिंग सर्विस

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। प्राइस वॉर का नुकसान झेल चुकी एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियां अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही हैं। रिलायंस जियो द्वारा दिए गए ऑफर्स के चलते इन कंपनियों को लगातार ग्राहकों को फ्री और सस्ती कॉल्स देकर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब इस नुकसान से बचने के लिए कंपनियों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। यह कंपनिया जल्द ही फ्री इनकमिंग सर्विस को बंद कर सकती हैं। साथ ही कंपनियों ने इसके लिए मिनिमम रिचार्ज प्लान भी जारी किए है। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक, वोडाफोन और एयरटेल अपने एवरेज पर रेवेन्यू को बढाने पर खासा जोर दे रही हैं।

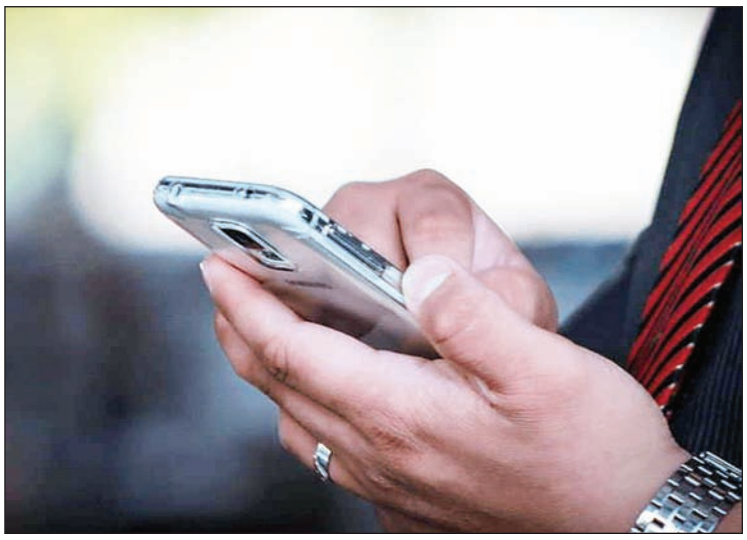

एयरटेल और वोडाफोन ने जारी किए नए प्लान

टेलीकॉम कंपनियों ने इनकमिंग सर्विस के लिए 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान जारी किए हैं। इसके तहत अब यूजर्स को इनकमिंग कॉल के लिए भी हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा। कंपनियों ने इसके लिए नए तरह के प्लान जारी किए हैं। जिसमें 35 रुपए, 65 रुपए और 95 रुपए के प्लान हैं। इन तीनों प्लान की वैलिडिटी 28 दिन तक होगी। और वैलिडिटी खत्म होने के बाद फोन की आउटगोइंग सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। कंपनियां ग्राहकों की इनकमिंग सर्विस बंद करने के लिए उन्हें थोड़ा समय देंगी।

इनकमिंग पर अपना कनेक्शन चला रहे ग्राहकों के लिए कंपनियों ने लिया फैसला

कंपनी ने इनकमिंग सर्विस बंद करने का यह निर्णय उन ग्राहकों को देखते हुए लिया है, जो सिर्फ इनकमिंग पर अपना कनेक्शन चला रहे हैं। या फिर सिर्फ काम के समय फोन में कम से कम रुपए का रिचार्ज कराते हैं। ऐसे यूजर्स के कारण कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इनकमिंग कॉल के लिए करना होगा रिचार्ज

वोडाफोन इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, टेलीकॉम सेक्टर को इस वक्त प्राइस वॉर ने घेरा हुआ है। इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। कंपनियों ने कहा कि अब इनकमिंग जारी रखने के लिए महीने में एक बार रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज की तारीख के 45 दिन तक इनकमिंग सर्विस बंद नहीं होगी। लेकिन, इसके बाद रिचार्ज नहीं कराने पर सर्विस बंद कर दी जाएगी।

रेलवे के रूप में जियो को मिला सबसे बड़ा ग्राहक, 1 जनवरी से मुहैया कराएगा सेवाएं

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

दिल्ली। रिलायंस जियो इंफोकॉम एक जनवरी से भारतीय रेलवे को अपनी सेवाएं मुहैया कराएगा. इस तरह जियो को रेलवे के रूप में अपना सबसे बड़ा ग्राहक मिल गया है, जबकि अधिकारियों के मुताबिक इस गठजोड़ से रेलवे के फोन बिल में 35 प्रतिशत की कमी आएगी. अधिकारियों ने बताया कि रेलवे पिछले छह वर्षों से भारती एयरटेल की सेवाएं ले रहा है, जो रेलवे के कर्मचारियों को 1.95 लाख मोबाइल कनेक्शन मुहैया कराता है. इनका इस्तेमाल क्लोज ग्रुप यूजर (सीयूजी) के तौर पर किया जाता है. उन्होंने बताया कि इसके लिए रेलवे हर साल करीब 100 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान करता है. इसकी वैलिडिटी इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. रेलवे बोर्ड द्वारा 20 नवंबर को जारी एक आदेश में कहा गया है, श्रेलटेल को ये जिम्मेदारी दी गई था कि भारतीय रेलवे के लिए फ्रेश सीयूजी स्कीम को अंतिम रूप दे, क्योंकि मौजूदा स्कीम 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो रही थी. नई सीयूजी स्कीम को रेलटेल ने अंतिम रूप दिया है और रिलायंस जियो इंफोकॉम को योजना लागू करने का ठेका दिया गया है.

सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का प्लान ठंडे बस्ते में डाला, कहा सुधारेंगे हालत

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को केंद्रीय उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल निवेश का फैसला नहीं लिया गया है. हम एयरलाइन की हालत सुधारने पर ध्यान देंगे. जयंत सिन्हा ने कहा, एयरलाइन इंडस्ट्री की हालत को देखते हुए हम फिलहाल निवेश का फैसला नहीं ले रहे हैं. इसकी बजाय हम एयरलाइन के रिवाइल प्लान पर काम करेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले दबी एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में जुटी थी.

हालांकि इस डील पर अभी कोई सार्थक पहल हो नहीं सकी है. इसी साल मई में एयर इंडिया को बेचने की खातिर केंद्र सरकार ने 160 प्रश्नों का उत्तर देकर सभी शंकाएं दूर की थीं. लेकिन उसके बाद भी अभी किसी प्लेयर ने इस डील में खास रुचि नहीं दिखाई है.

केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है. जिसमें 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास ही रहेगी. इस तरह सरकार ने खुद के लिए एयरलाइन के कामकाज में शामिल होने के लिए दरवाजे खुले रखे हैं. सिर्फ यही एक वजह नहीं है, जिससे खरीदार दूर भाग रहे हैं. इसके अलावा जो भी एयर इंडिया खरीदेगा. उसे एयरलाइन के 48,781 करोड़ के कर्ज में से 33,392 करोड़ रुपये का कर्ज भी अपने ऊपर लेना होगा.

ग्लोबल टी मार्केट में भारत को कड़ी टक्कर दे रहा केन्या

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। केन्या में चाय की रेकॉर्ड फसल होने के कारण वैश्विक बाजार में भारत की चाय को कड़ा मुकाबला मिल रहा है। केन्या के अपना उत्पादन चाय की अधिक खपत करने वाले यूरोप, पाकिस्तान और मिस्र में भेजने के कारण भारत की चाय को अधिक कीमतें नहीं मिल रही।

2018 की पहली छमाही में भारतीय चाय की कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10 पर्सेंट अधिक थी, लेकिन दूसरी छमाही में इनमें काफी कमी आई है। इंडस्ट्री के एग्जिक्यूटिव्स का मानना है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के 24.06 करोड़ किलोग्राम के एक्सपोर्ट को पार करना मुश्किल होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट में केन्या की पकड़ मजबूत है। मैकलॉयड रसेल इंडिया के डायरेक्टर अजम मोनेम ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, इस वर्ष केन्या की फसल लगभग 49 करोड़ किलोग्राम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 43 करोड़ किलोग्राम थी। केन्या में अच्छी बारिश होने के कारण जुलाई से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे उसे अधिक एक्सपोर्ट करने में मदद मिल रही है।

2018 के पहले नौ महीनों में भारतीय चाय का उत्पादन 94.18 करोड़ किलोग्राम रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लगभग समान है। मोनेम ने कहा कि इस वर्ष एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। इसके पीछे केन्या में उत्पादन बढ़ना और चाय के एक बड़े मार्केट ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मार्केट में अनिश्चितता प्रमुख कारण हैं।

टी बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश ने 17.38 करोड़ किलोग्राम चाय का एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के बराबर है। ईरान को लेकर अनिश्चितता के कारण ऑर्थोडॉक्स टी का उत्पादन करने वाले सीटीसी टी की ओर शिफ्ट हुए हैं।

मोनेम ने बताया, ईरान पर प्रतिबंधों को लेकर भारत को अमेरिका से कुछ छूट मिलने से रुपये–रियाल में व्यापार जारी है। हालांकि, टी प्रोड्यूसर्स के सीटीसी की ओर शिफ्ट होने से वे मौजूदा स्थिति का फायदा नहीं उठा पा रहे। इससे ग्लोबल मार्केट में सीटीसी टी की सप्लाई बढ़ी है और प्राइसेज कम हुए हैं।

सीनियर टैलंट की तलाश में ई-कॉमर्स, स्टार्टअप सेक्टर

उद्योग विहार (नवंबर–2018)

नई दिल्ली। सीनियर टैलंट के लिए भले ही सामान्य जॉब मार्केट ठंडा हो, लेकिन ईकॉमर्स और स्टार्टअप सेक्टर में कहानी बिल्कुल अलग है। बेहतर फंडिंग, मर्जर ऐंड एक्विजिशन से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ोतरी, मोबाइल डेटा के इस्तेमाल में बंपर उछाल, ई–कॉमर्स सेक्टर के मैच्योर होने के चलते इनकी ग्रोथ काफी तेज हुई है। ये कंपनियां टॉप लेवल पर सीनियर टैलंट को हायर कर रही हैं। एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, पेटीएम, ओयो, ओला या जोमैटो हो या हाल ही में पहले या दूसरे राउंड का फंड जुटाने वाली स्टार्टअप, सब सीनियर टैलंट को हायर कर रही हैं। सर्च फर्मो ने बताया कि पिछले एक साल में इन सेक्टर में सीनियर टैलंट की हायरिंग में 40 से 100 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। फिडियुस एडवाइजरी के मैनेजिंग पार्टनर, अनुज रॉय ने बताया, श्ऑनलाइन सेक्टर में हायरिंग तेजी से बढ़ी है।श उनकी कंपनी से 13–14 सीनियर टैलंट के लिए संपर्क किया गया है, जिनकी संख्या पिछले साल 7 से 8 थी। बेंगलुरु के लॉन्गहाउस कंसल्टिंग को कंपनियों ने पिछली तिमाही में 30 सीनियर टैलंट्स ढूंढने को कहा था। इस तिमाही में यह संख्या 75 हो गई है। इनमें से ज्यादातर ई–कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं। रॉय ने कहा कि सीनियर टैलंट की हायरिंग में बढ़ोतरी घरेलू स्टार्टअप सिस्टम में तेजी को दिखाती है। कंसल्टेंट्स का कहना है कि पिछले 6–7 महीनों में हायरिंग तेज हुई है। एक आकलन के मुताबिक, इस दौरान ई–कॉमर्स और स्टार्टअप सेक्टर में करीब 350 से 400 सीनियर टैलंट की हायरिंग हुई है। सिर्फ पिछले हफ्ते में ओयो होटल्स ने इंडिगो के पूर्व प्रेसिडेंट आदित्य घोष को अपने इंडिया और साउथ एशिया बिजनस का सीईओ नियुक्त किया। फ्लिपकार्ट ने स्मृति सिंह को ह्यूमन रिसोर्स के हेड के रूप में हायर किया। मेकमायट्रिप ने विपुल प्रकाश को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। फ्रेशवर्क ने दो सीनियर लेवल पर हायरिंग की। यहां तक कि दूधवाला जैसी छोटी स्टार्टअप ने भी सीएक्सओ रोल में अप्वाइंटमेंट किए हैं। कंसल्टेंट्स ने बताया कि हाल में बनी कंपनी से लेकर यूनिकॉर्न तक टॉप टैलंट को हायर कर रही हैं। एक तरह फ्लिपकार्ट, एमेजॉन और स्विगी जैसी कंपनियां हैं, जिन्होंने हायरिंग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है।

क्लास रूम में बनी सांप-सीढ़ी पर गणित सीख रहे बच्चे

बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल गांव मढ़ना के सरकारी प्राथमिक स्कूल ने बच्चों को अंग्रेजी और गणित सिखाने का रोचक तरीका ढूंढ निकाला। बिलासपुर जिले के गौरेला ब्लॉक स्थित इस गांव में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों ने कक्षा में विशेष सांप-सीढ़ी बनाई। इस पर उकेरे गए अंकों और अक्षरों के जरिये बच्चे जोड़-घटाना-गुणा-भाग तो सीख ही रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द और वाक्य भी बना रहे हैं। अब पहाड़ा सभी बच्चों को कंठस्थ हो चुका है। वे स्कूल में अंग्रेजी में ही बात करने का अभ्यास भी करने लगे हैं। सभी इसका श्रेय प्रधान पाठक राधेश्याम चतुर्वेदी को देते हैं, जिनका यह आइडिया था। सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ढर्रे से परे इस स्कूल के बच्चे खेल-खेल में पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनमें शिक्षा को लेकर रुचि उत्पन्न हो गई है। कक्षा में फर्श पर बनाई गई सांप-सीढ़ी देखने में जितनी आकर्षक है, इस पर पढ़ाई का तरीका उतना ही मजेदार। एक-एक कर बच्चों को सांप-सीढ़ी पर उतारा जाता है। इसके जरिए पहाड़ा, अंकों का जोड़ना-घटाना, अंग्रेजी में शब्द-वाक्य रचना आदि सीखना बच्चों को बहुत पसंद आता है। सभी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सभी बच्चों को 20 तक का पहाड़ा कंठस्थ है। स्कूल परिसर में सभी अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करते हैं। स्कूल में कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई होती है। अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से हैं। छात्रों की संख्या फिलहाल 25 ही है, लेकिन यह अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। पहाड़ों व जंगलों के बीच आदिवासी इलाके में स्थित इस स्कूल में अन्य बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मसलन, परिसर में सभी बच्चों के नाम से पौधे लगाए गए हैं। बच्चे अपने नाम के पौधों में पानी देते हैं। सूचना पटल पर शिक्षकों की योग्यता और उनके फोन नंबर अंकित हैं। सुबह प्रार्थना के साथ व्यायाम और योगाभ्यास कराया जाता है। बच्चों को गणित और अंग्रेजी में निपुण बनाने के अलावा सामान्य ज्ञान पर भी शिक्षक जोर दे रहे हैं।

पाकिस्तानी बच्चे को भारत में मिला जीवनदान

नई दिल्ली, एजेंसी। यह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लेकिन यह हुआ है। पाकिस्तान के 14 माह के बच्चे के असामान्य हृदय रोग का जटिल ऑपरेशन सर गंगा राम अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया है। बीमारी की असामान्य प्रकृति के कारण बच्चे के माता-पिता उसे भारत लेकर आए थे। इस बच्चे का दिल असामान्य रूप से बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक, दिल के बाएं हिस्से की एट्रियम (जिससे फेफड़ों से साफ खून पहुंचकर इस जगह पर इकट्ठा होता है) गुब्बारे की तरह फूल गई थी। इस फुलाव के कारण एट्रियम के ऊपर मौजूद सांस की धमनियों को भी नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही थीं। लेफ्ट एट्रियम में खून की मात्रा आमतौर पर 12 से 20 मिलीलीटर होनी चाहिए, जबकि बच्चे में यह 87 मिलीलीटर तक थी। इस ऑपरेशन को चार डॉक्टरों की टीम ने पांच घंटे में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अस्पताल में पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के चेयरमैन डॉ. राजा जोशी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नीरज अग्रवाल और डॉ. मृदुल अग्रवाल और एनेस्थीशिया की डॉक्टर रीना खंतवाल ने ऑपरेशन को पूरा किया। इस ऑपरेशन से जुड़ा अनोखा अध्ययन केस दी एनल्स ऑफ थोरेसिक सर्जरी नाम के अमेरिका के हृदय सर्जरी से जुड़े मशहूर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के चेयरमैन डॉ. राजा जोशी के मुताबिक इस बच्चे का वॉल्व वह जन्म से खराब था। इससे खून के संचालन में भी कमी आ रही थी। ऑपरेशन से पहले यह बच्चा पाकिस्तान में हर 20 दिनों में किसी ना किसी बीमारी की वजह से भर्ती हुआ करता था। अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ्य है। डॉ. जोशी के मुताबिक इसके अलावा बच्चे के दिल में बड़ा छेद था। बाएं तरफ का वाल्व भी लीक हो रहा था।

सीलिंग मामले में सुप्रीमकोर्ट का सुनवाई से इंकार, कहा- मनोज तिवारी का बर्ताव गलत

नई दिल्ली, एजेंसी। सीलिंग तोड़ने के मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी। कोर्ट का कहना है कि उन्हें तिवारी द्वारा अदालत का किसी तरह की अवमानना किए जाने का मामला नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा चाहे तो इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने परिसरों पर लगी नगर निकाय की सील उनके द्वारा तोड़े जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने के मनोज तिवारी के बर्ताव से वह बहुत आहत हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था न कि कानून को अपने हाथ में लेकर। कोर्ट ने इस मामले में दलीलें सुनने के बाद 30 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को यह तय करना था कि तिवारी कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं या नहीं। आखिर आपको सील तोड़ने की इजाजत किसने दी अगर सीलिंग गलत की गई थी तो आपको संबंधित अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था।

सिख विरोधी दंगा मामलों में सक्रियता से काम कर रही है एसआईटी : जेटली

नयी दिल्ली, एजेंसी। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में भूमिका के कारण एक व्यक्ति को मृत्युदंड का अदालत द्वारा आदेश दिए जाने के एक दिन बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि अन्य संबंधित मामलों पर भी सक्रियता से काम किया जा रहा है। हालांकि दोषसिद्धि से पीड़ितों के परिवारों को मात्र थोड़ी ही सांत्वना मिलेगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दिल्ली तथा अन्य राज्यों में सिख विरोधी दंगे हुए थे तथा इनमें 3000 लोगों की जान गयी थी। ''आपरेशन ब्लू स्टार'' को एक ''ऐतिहासिक भूल'' बताते हुए जेटली ने कहा कि 1984 से 1998 के बीच की अवधि को दबाने-छिपाने वाला दौर कहा जा सकता है जिसमें सभी मामलों को दबा दिया गया-मानों 1984 का नरसंहार हुआ ही न हो। जेटली ने अपने ब्लाग में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी पहली राजग सरकार ने न्यायमूर्ति जीटी नानावती जांच आयोग को नियुक्त किया था जिसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश का दायित्व दिया गया। एक बार फिर यह नरेन्द्र मोदी सरकार है जिसने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीपी माथुर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन 2015 में किया। एसआईटी ने कई ऐसे मामलों का पता लगाया जहां आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी थे किन्तु उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किए गए। उन्होंने कहा, ''कल दिल्ली की अदालत ने जिस मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया और उनमें से एक को मृत्युदंड दिया गया, उसका अभियोजन दशकों बाद इस एसआईटी ने किया।'' वित्त मंत्री ने कहा, ''बाद में इस एसआईटी का स्थान एक अन्य एसआईटी ने लिया जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। बाद वाली एसआईटी को उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त किया था।'' उन्होंने कहा कि कल एक मामले में न्याय किया गया है तथा हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें 1980 के दशक में ही दण्ड मिल सकता था।

जेटली ने कहा, ''एक मामले में सफलता मिली है। भारतीय समाज विशेषकर सिख समुदाय 1984 की भयावह स्मृतियों से मुक्त होना चाहता है।'' ''1984 की विरासत'' शीर्षक वाली पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में जून 1984 में हुए भीषण आपरेशन का प्रत्यक्ष परिणाम प्रधानमंत्री की हत्या थी। उन्होंने कहा, ''यह भारतीय इतिहास के सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण और भर्त्सना योग्य कृत्यों में से एक है। इससे शासन की विफलता भी इंगित होती है। इसके परिणामों पर पहले से विचार नहीं किया गया था। यह विनाशकारी साबित हुआ।'' जेटली ने कहा, ''कांग्रेस जनों ने 'खून का बदला खून' के नारे लगा रहे शोकाकुल लोगों एवं प्रदर्शनकारियों के समूहों की अगुवाई की। दूरदर्शन पर 24 घंटे चलने वाले प्रसारण में इस भड़काऊ नारे को दिखाया जा रहा था।'' उन्होंने कहा कि सिख विरोधी दंगे देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हो गये। दिल्ली सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। वित्त मंत्री ने कहा, ''कांग्रेस जनों ने हिंसक भीड़ की अगुवाई की।'' पुलिस ने उनका साथ दिया तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए न तो लाठियां चलायी गयी, न आंसू गैस छोड़ी गयी और ना ही गोलियां चलायी गयीं। उन्होंने कहा, ''दंगाइयों को मारने एवं लूटने की खुली छूट दी गयी। सिख समुदाय के पूजा स्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया। सिख मकानों को जला दिया गया। उनके व्यापार प्रतिष्ठानों को लूटा गया। हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को जला दिया गया या उनके अंगभंग किये गये। पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की।'' आपरेशन ब्लू स्टार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''इसकी बहुत खराब योजना बनायी गयी और इसे भीषण ढंग से क्रियान्वित किया गया। उग्रवादियों की संख्या तथा उनके द्वारा एकत्र किए गए हथियारों के बारे में कोई खुफिया सुराग नहीं था।'' जेटली ने कहा, ''ब्लूस्टार भारत के सर्वाधिक देशभक्त समुदाय की भावनाओं को आहत करने में कामयाब हुआ। संकुचित दृष्टिकोण वाली एक सरकार ने इस कदम की राजनीतिक कीमत के बारे में भी विचार नहीं किया।

मां-बाप ने मरा हुआ समझ लिया था, 6 महीने बाद सही-सलामत मिली बच्ची

नई दिल्ली, एजेंसी। परिवार के लोगों ने साढ़े तीन साल की जिस मूक और बधिर बच्ची को मृत समझ लिया था, छह महीने बाद वह जिंदा मिली। छह महीने बाद बच्ची ने जब अपनी आंखों के सामने अपने पैरंट्स को देखा तो वह दौड़कर उनसे चिपक गई। बच्ची को सही-सलामत अपनी गोद में पाकर पैरंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं। परिवारवालों ने इसका पूरा श्रेय ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दिया। उनका कहना था कि वे लोग तो यह उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि अबतक बच्ची जिंदा होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फरिश्ते की तरह दोबारा बच्ची को उनकी गोद में डाल दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, अताउल्ला अंसारी पत्नी रूबीना खातून और साढ़े तीन साल की बेटी के साथ अलीपुर इलाके में सिंघू गांव में रहते हैं। पति-पत्नी दोनों वहीं आसपास की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। 14 मई 2018 को उनका पूरा परिवार चंपारण, बिहार स्थित अपने गांव जाने के लिए घर से निकला था। सभी लोग ट्रेन लेने के लिए आनंद विहार बस अड्डे के सामने ईडीएम मॉल के पास पहुंचे थे। अताउल्ला अंसारी, पत्नी और अपने भाई को वहीं पर खड़ा छोड़कर बेटी को साथ लेकर टिकट लेने की बात कहकर वहां से चले गए लेकिन दोनों नहीं लौटे। परिवारवालों ने यहां-वहां खूब खोजा, लेकिन बाप-बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। फिर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। फिर बाकी लोग वहां से वापस लौट गए। करीब 9 दिनों बाद बच्ची का पिता वापस आ गया, लेकिन बच्ची के बारे में बता नहीं सका, क्योंकि उसकी भी मानसिक हालत ठीक नहीं है।

डीसीपी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच डिस्ट्रिक्ट की ऐंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंपी गई। एसीपी विनीता त्यागी की देखरेख में इंस्पेक्टर विदेश सिंघल, एएसआई सुधीर, सुभाष, योगेंद्र और हेड कॉन्स्टेबल राजपाल सहित अन्य पुलिसवालों की टीम लगातार बच्ची की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि इसी हुलिये से मिलती-जुलती बच्ची गाजियाबाद के संजय नगर में स्थित प्रेरणा बाल आश्रम में देखी गई है। पुलिस ने बच्ची को आश्रम से बरामद कर लिया। जैसा परिवारवालों ने बताया था कि उनकी साढ़े तीन साल की बेटी बोल और सुन नहीं सकती, यह बच्ची भी बोलने और सुनने में असमर्थ है। बच्ची के पैरंट्स को भी बुलाया गया, उन्होंने अपनी बच्ची को पहचान लिया। पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने पेश किया। वहां से बच्ची को उसके पैरंट्स को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दंपती की वह इकलौती संतान है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की टोल नीति में बदलाव कर सरकार देगी ट्रांसपोर्टरों को राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मौजूदा टोल नीति में संशोधन का विचार कर रही है। इसे आम लोगों के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों और कारपोरेट सेक्टर के लिए राहतकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक मशहूर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एजेंसी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की सेवाएं ली गई हैं जो मौजूदा नीति की समीक्षा कर छह महीने में अपने सुझाव देगी। सड़क मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मुताबिक बीसीजी से कहा गया है कि नीति को अंतरराष्ट्रीय चलन और मानकों के अनुरूप ढालने के साथ-साथ सभी स्टेकहोल्डर के लिए संतुष्टिकारक बनाने के लिए जरूरी सुझाव दे। बीसीजी टोल दर निर्धारण के मौजूदा फार्मूले पर भी विचार करेगी। जिसमें थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर हर वर्ष अप्रैल में टोल दरों में संशोधन का प्रावधान है। बीते अप्रैल में एनएचएआइ ने इसी आधार पर पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की टोल दरों में 5 फीसद की बढ़ोतरी की थी।

मौजूदा नीति में दो लेन के हाईवे पर चार लेन हाईवे के मुकाबले 60 फीसद टोल वसूलने की व्यवस्था है। बीसीजी इसके औचित्य की भी जांच करेगी। साथ ही जिन 25 किस्म के विशिष्ट व्यक्तियों तथा सात किस्म के वाहनों को टोल से छूट दी गई है।

प्लेन में मंत्री जयंत सिन्हा को एयरहोस्टेस ने स्नैक्स देने से मना किया तो पैसे देकर खरीदा

नई दिल्ली, एजेंसी। विमान यात्रा के दौरान मर्यादित व्यवहार को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मिसाल पेश की है। दरअसल, जयंत सिन्हा मंगलवार को एयरएशिया की फ्लाइट से दिल्ली से रांची की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एयरहोस्टेस से स्नैक्स के लिए अनुरोध किया लेकिन एयरहोस्टेस ने उनके अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने लिए खाद्य सामग्री पहले ही बुक करा ली है और अंत समय में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद सिन्हा को पैसे देकर स्नैक्स खरीदना पड़े। केंद्रीय मंत्री ने आम यात्री की तरह अलग से पैसे देकर अपने लिए स्नैक्स खरीदा। इस घटना का जिक्र केंद्रीय मंत्री के साथ वाली सीट पर यात्रा करने वाले यात्री ने की है। उस यात्री ने कहा, विमान के चालक दल के सदस्यों को अपने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री को पहचानने की जरूरत है। आज मैं दिल्ली से रांची जाने वाले विमान आई5-545 में जयंत सिन्हा की बगल वाली सीट पर बैठा था। यात्रा के दौरान सिन्हा ने स्नैक्स की मांग की लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्होंने पहले ही दक्षिण भारतीय खाने की बुकिंग की है और इसे अब बदला नहीं जा सकता। इसके बाद जयंत सिन्हा ने पैसे देकर स्नैक्स खरीदे। ट्विटर पर एयरएशिया के इस पेशेवर व्यवहार और जयंत सिन्हा के बर्ताव की प्रशंसा हो रही है। एक व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए दोनों विमान कंपनी और जयंत सिन्हा की प्रशंसा होनी चाहिए। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि विमान कंपनी को कम से कम अपने विभाग के मंत्री को पहचानना चाहिए।

2017-18 में बीजेपी को 400 करोड़ से अधिक चंदा मिला, कांग्रेस ने जुटाए सिर्फ 26 करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग को सौंपी गई अपनी हालिया कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में बीजेपी ने बताया है कि 2017-18 में उसने 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। यह रकम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लगभग 15 गुना ज्यादा है।

राजनीतिक दलों के कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स की समीक्षा से यह बात सामने आई है। इससे पता चला कि पिछले वित्त वर्ष में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी सिर्फ 26 करोड़ रुपये जुटा पाई थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के ऐनुअल ऑडिट अकाउंट्स में इस रकम में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि फुल ऑडिटेड रिपोर्ट आने पर बीजेपी के लिए यह रकम 1,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी तक 2017-18 के ऐनुअल ऑडिटेड इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट फाइल नहीं की है।

राजनीतिक दलों ने अभी तक इलेक्टोरल बेस्ड फंडिंग की भी जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस और बीजेपी के ऐनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स में इसकी जानकारी भी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस रास्ते से बीजेपी कहीं ज्यादा फंड जुटाएगी। उसे प्रूडेंट इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट से 144 करोड़ से अधिक रकम मिली है, जिसने 2017-18 में करीब 169 करोड़ रुपये जुटाए थे। कांग्रेस को 1 करोड़ देने वाले आदित्य बिड़ला जनरल इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 12 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए हैं। मुरुगप्पा ग्रुप के ट्रायंफ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 करोड़ रुपये दिए हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के अलावा कैडिला हेल्थकेयर (13 करोड़ से अधिक), माइक्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड (हरेक ने 9-9 करोड़), सिप्ला (9 करोड़) और एलेंबिक फार्मास्युटिकल्स और महावीर मेडिकेट (6 करोड़) बीजेपी के बड़े कंट्रीब्यूटर्स में शामिल हैं। लोढ़ा (6.5 करोड़), जे कुमार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स (5 करोड़) और रेयर एंटरप्राइजेज (9 करोड़) ने भी बीजेपी की फंडिंग की है।

2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से पार्टी की योगदान राशि 2013-14 के 673.81 करोड़ से 53त्न बढ़कर 2016-2017 में 1,034.27 करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि में कांग्रेस की कमाई 598.06 करोड़ से 62त्न गिरकर 225.36 करोड़ रह गई। सत्ताधारी पार्टियां आमतौर पर दूसरे दलों से अधिक फंड जुटाती रही हैं।

तीसरा मोर्चा नहीं, लेकिन कई सीटों पर बड़े दलों को मुश्किल

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के सामने तीसरा मोर्चा नहीं बन पाया लेकिन कई सीटों पर छोटे मोटे दलों ने मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत वाहिनी एवं आम आदमी पार्टी ,बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट दल एक होकर तीसरे मोर्चे की शक्ल नहीं दे पाए लेकिन उनके कई उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। भारत वाहिनी ने 75 बसपा ने 198 और राष्ट्रवादी पार्टी ने 68 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे है। नामांकन वापस लेने की तारीख पर ही सही तस्वीर आयेगी लेकिन मौजूदा हालात में मुकाबला त्रिकोणात्मक के साथ चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जाट बाहुल्य स्थानों पर कांग्रेस और भाजपा को पसीनें लाने की स्थिति में खड़ा कर दिया है। किसान आंदोलन के जरिए नागौर ,सीकर ,बाड़मेर ,जोधपुर जिलों में पहले से ही जमीन मजबूत कर इस दल ने दोनों प्रमुख दलों के टिकट से वंचित रहे नेताओं को भी उम्मीदवार बनाकर स्थिति मजबूत की है।

एक दूसरे को बचा रही हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां

इस पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा को सत्ता देने की परंपरा पर भी जोरदार चोट करते हुए कहा है कि इससे भ्रष्टाचार पनप रहा है तथा दोनों एक दूसरे को बचा लेते है। बेनीवाल ने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए खेल तथा फिल्मों में जाट समुदाय की बड़ी हस्तियों को बुलाकर अपनी स्थिति और मजबूत करने का प्रयास कर रहे है। इसी पार्टी की टिकट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल, कांग्रेस की नेता प्रतिभा सिंह सहित कई उम्मीदवार मैदान में है। भारत वाहिनी पार्टी ने भी भाजपा से नाराज नेताओं को जोडने का प्रयास किया है। इस पार्टी के कर्ताधर्ता घनश्याम तिवाड़ी ने राष्ट्रवादी पार्टी से समझौता कर चुनाव में ताकत दिखाने का प्रयास किया है। तिवाड़ी स्वयं सांगानेर से चुनाव लड़ रहे है तथा भाजपा की टिकट से वंचित रहे विधायक किसनाराम नाइक तथा सिकराय से विधायक गीता वर्मा सहित कई नेताओं को चुनाव मैदान में उतारकर प्रमुख दलों को शिकस्त देने का प्रयास किया है। बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक नवीन पिलानिया को आमेर से खड़ा किया है।

बसपा विधायक आजमा रहे हैं फिर अपना भाग्य : इसके अलावा सूरतगढ़ में पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे डूंगरराम गेदर तथा किशनगढ़बास से दीपचंद खेरिया को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बसपा ने सूरजगढ़ से कर्मवीर यादव, पिलानी से जया कटारिया तथा खेतड़ी से पूरणमल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। सैनी ने पिछला चुनाव बसपा के टिकट पर ही जीता था। सादुलपुर से बसपा विधायक मनोज न्यागली फिर अपना भाग्य आजमा रहे है। कम्युनिस्ट पार्टी आफॅ इंडिया तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छोटे मोटे दलों के साथ मोर्चा बनाया है, लेकिन गंगानगर, सीकर,झुंझुनूं तथा आदिवासी क्षेत्रों में ही कुछ सीटों पर इनका प्रभाव माना जा रहा है। मार्क्सवादी पार्टी के नेता अमराराम दातारामगढ़ से चुनाव मैदान में है। पिछली बार वह तीसरे स्थान पर रहे थे।

माकपा के पूर्व विधायक पेमाराम भी धोद विधानसभा से चुनाव मैदान में है। कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी का टिकट कटने के बाद दूसरे दल का सहारा नहीं लिया तथा निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इनमे वसुंधरा सरकार में मंत्री राजकुमार रिणवा रतनगढ़ से हेम सिंह भडाना, थानागाजी से धनसिंह रावत बांसवाड़ा से विधायक अनिता कटारा सागवाड़ा से नवनीत लाल निनामा घाटोल से तथा कांग्रेस के पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला के साथ वसुंधरा सरकार में मंत्री सुरेन्द्र गोयल जैतारण से शामिल है।

जातिगत संगठनों के साथ बैठक करके विवाद सुलझाएंगे सीएम विजयन

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। सबरीमाला विवाद को लेकर अब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन नई रणनीति अपनाएंगे। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि अब वह नायर सर्विस सोसायटी और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जैसे जातिगत संगठनों के साथ बैठक करेंगे। इधर त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड ने भी साफ किया है कि वह सबरीमाला विवाद को सुलझाने के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। एक टेलिविजन शो में इंटरव्यू के दौरान सीएम ने कहा कि पुनर्जागरण आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी संगठनों को इस समय एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा, सबरीमाला में शांति वापस लाने के लिए सरकार इन संगठनों के साथ बात करने को तैयार है। प्राचीनकाल में सबरीमाला को वापस ले जाने का प्रयास राज्य का अपमान है। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए

उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्जागरण अवधि के मूल्यों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध थी और इसके लिए राज्य में अकादमिक पाठ्यक्रमों को संशोधित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, टीडीबी भी धार्मिक पहाड़ी में फिर से शांति बरकरार रखने के लिए बातचीत के दरवाजे खोलने को तैयार है। टीडीबी अध्यक्ष ए पद्मकुमार ने कहा कि सबरीमाला को घटनाओं से मुक्त होना चाहिए और हम इसके लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पारिक समाचार पत्र

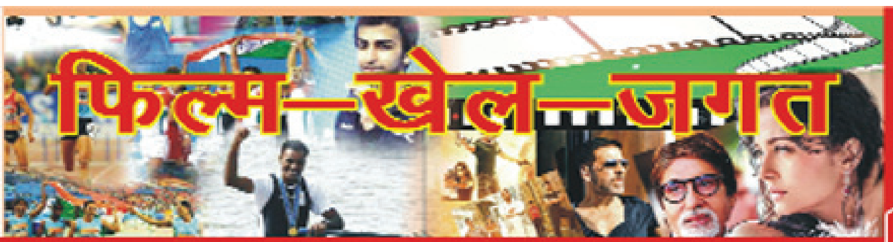

08 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, नवंबर, 2018

जीरो में अनुष्का के अभिनय की कायल हुई कैटरीना

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ फिल्म जीरो में अनुष्का शर्मा के अभिनय की कायल हो गई है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म जीरो में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ ने अहम भूमिका निभाई है। कैटरीना ने बताया कि वह फिल्म जीरो में अनुष्का शर्मा के अभिनय से इतनी प्रभावित थी कि उसे देख कर रो दिया करती थी। उन्होंने कहा, इस फिल्म की कहानी सबसे पहले उनके पास आई थी। फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय ने मुझसे कहा था कि मेरी भूमिका फिल्म में सबसे दमदार है, जिसे सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म जीरो में मेरा सबसे पसंदीदा रोल अनुष्का शर्मा का है। जब मैंने अनुष्का को फिल्म के सेट पर उस भूमिका में डूबा हुआ पाया तो मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकी। कैटरीना ने कहा, यदि आपको इस बात का विश्वास ना हो तो आप फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय से पूछ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि फिल्म में शाहरुख खान ने बौने की भूमिका निभाई है। फिल्म जीरो 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

आनंद ने बंद की ऋतिक टाइगर और वानी के साथ शूटिंग

बॉलीवुड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग बंद कर दी है। आनंद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया और लिखा, शूटिंग समाप्त हुई! एक शानदार टीम के साथ बड़ा शूट हुआ जिसके लिए हम कई शहर और देश घूमे और विभिन्न प्रकार के वातावरण तथा खराब मौसम का सामना किया। दिवाली के समय पर घर वापस! शूटिंग दोबारा शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। फिल्म का नाम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि यह एक एक्शन–थ्रिलर है। यश चोपड़ा की 85वीं वर्षगांठ पर 27 सितंबर को यश राज फिल्मस ने इस फिल्म की घोषणा की थी। आनंद ने ऋतिक के साथ 'बैंग बैंग' में काम किया है और 'सलाम नमस्ते', 'ता रा रम पम', 'बचना ए हसीनो' तथा 'अनजाना अनजानी' में भी काम कर चुके हैं।

आखिर क्यों आमिर खुद लिखते हैं फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि आमिर खान फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। अमिताभ और आमिर ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान में साथ काम किया है। यशराज बैनर तले बनी यह फिल्म आज रिलीज हुई। आमिर हाल ही में अमिताभ के शो कौन बनेगा करोड़पति पर पहुंचे थे। आमिर एक अन्य प्रतिभागी के साथ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे। शो के दौरान दोनों कलाकारों ने एक–दूसरे के साथ काफी मस्ती–मजाक भी किया। अमिताभ बच्चन ने ठग्स ऑफ हिंदोस्तान के दौरान आमिर के साथ बिताए समय का काक्रि करते हुए बताया कि आमिर जब किसी फिल्म को करते हैं तो निर्माता द्वारा दी गयी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पूरी स्क्रिप्ट को अपनी अलग डायरी में खुद लिखते हैं और उसी से तैयारी करते हैं। इस बारे में आमिर ने कहा कि खुद लिखने से उन्हें स्क्रिप्ट याद हो जाती है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं।

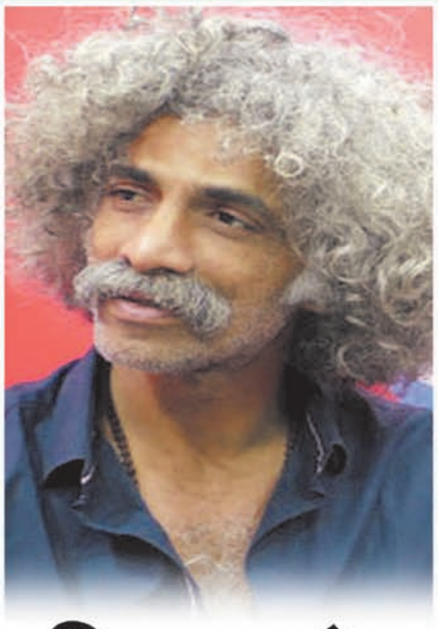

थिअटर के चलते फिल्मों से दूर हो गया था

मकरंद देशपांडे ने फिल्मों और टीवी में कई यादगार रोल किए हैं। उन्हें एक बेहतरीन ऐक्टर माना जाता है लेकिन उन्होंने टेलिविजन और फिल्मों को छोड़कर थिअटर का रुख क्यों कर लिया? इस बारे में उन्होंने खुलकर बात की। सरफरोश, स्वदेश, मकड़ी, डरना जरूरी है जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय करने वाले अभिनेता मकरंद देशपांडे एक लंबे अरसे बाद टीवी शो 'विक्रम बेताल' की रहस्य गाथा में नजर आ रहे हैं। ऐंड टीवी के इस शो में मकरंद बेताल की अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीवी से दूरी और इस शो के लिए हां कहने की वजह पूछने पर मकरंद कहते हैं, 'मैं टीवी से इसलिए दूर रहा, क्योंकि यहां वक्त की मांग बहुत ज्यादा है जबकि मैं ऐसा इंसान हूं, जिसे अपने लिए वक्त चाहिए। इसीलिए, मैं इससे दूर रहा। वरना, मुझे जो प्रसिद्धि मिली, वह टीवी से ही मिली है। वह चाहे 'सर्कस' हो या 'रिपोर्टर' हो, 'सैलाब' हो या 'वक्त की रफ्तार' हो, टीवी ने मुझे पैसे भी दिए और नाम भी दिया। रही बात बेताल का रोल करने की, तो रावण, कृष्ण, बेताल, ये ऐसे किरदार हैं जिन्हें आप मना कर ही नहीं सकते। इनके बारे में आप बचपन से सुनते रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये किरदार आपको निभाने के लिए मिलते हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं।' वैसे, मकरंद छोटे पर्दे से ही नहीं, बड़े पर्दे पर भी कम ही नजर आते हैं, इस पर उनका कहना है, 'फिल्मों से दूरी की वजह रंगमंच है। रंगमंच के कारण मैंने फिल्में करना कम कर दिया था। अब फिर फिल्में करना शुरू कर रहा हूं। दरअसल, पहले मुझे इतना धैर्य भी नहीं था कि सेट पर जाकर बैठूं। अब वह धैर्य आ गया है, तो मजा भी आ रहा है।' ऐक्टिंग के अलावा, मकरंद ने 'सोना स्पा', 'शाहरुख बोला खूबसूरत है तू' जैसी फिल्में निर्देशित भी कीं, जो नाकामयाब रहीं। इन फिल्मों के फ्लॉप होने का क्या असर पड़ा? यह पूछने पर वह बताते हैं, 'मैं जैसे सोचता हूं, शायद वह किसी को समझ में नहीं आया। ऐसे में आपके सामने दोराहे आते हैं क्योंकि हमारे लिए तो फिल्म आर्ट है, पर जो पैसा लगाता है, उसके लिए कॉमर्स है। लेकिन मैं बाजार के हिसाब से नहीं सोच पाता। ऐसे में आपको चुनना पड़ता है, तो मैं थिअटर को चुन लिया। वहां मैं अपने नाटक खुद प्रड्यूस करता हूं। थिअटर मेरे लिए जीने का जरिया बन चुका है। मुझे लगता है कि मेरे निजी सवालों के जवाब मुझे वहां मिलते हैं।'

ऐसा न हो कि लोग डरने लग जाएं

मकरंद इंडस्ट्री में चल रहे मीटू मूवमेंट को लेकर ज्यादा सकारात्मक नजर नहीं आए। इस मुद्दे पर उनका कहना है, 'अब जो है, वह है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वे बीस साल, दस साल, पांच साल के बाद बोल रही हैं। मेमरी में पीछे जाकर उस फ्रेम ऑफ माइंड में यह सोचना कि क्या घटा था, क्यों घटा था। फिर, इसमें कानून ही कार्रवाई कर सकता है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं। इतना ही बोल सकते हैं कि घटा था, तो गलत है। मुझे लगता है कि जैसे पहले फिल्मों, नाटकों में स्त्री पात्र पुरुष करते थे, क्योंकि स्त्री का यहां काम करना ठीक नहीं माना जाता था। अब ऐसी घटनाएं घटेंगी, तो मुझे लगता है कि धीरे–धीरे फिर वैसा न हो जाए। मतलब लोग डरेंगे, तो क्या करेंगे। ऐसा न हो जाए कि लोग डरने ही लग जाएं।'

अक्षय बनाएंगे भारत की पहली स्पेस फिल्म

बॉलिवुड ऐक्टर अक्षय कुमार ने फॉक्स स्टार स्टूडियो और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रड्यूस की जाने वाली तीन फिल्मों का करार किया है। इस साझेदारी में बनने वाली पहली फिल्म 'मिशन मंगल' होगी जो भारत की पहली स्पेस फिल्म होगी। बॉलिवुड ऐक्टर अक्षय कुमार ने फॉक्स स्टार स्टूडियो और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रड्यूस की जाने वाली तीन फिल्मों का करार किया है। इस साझेदारी में बनने वाली पहली फिल्म 'मिशन मंगल' होगी जो भारत की पहली स्पेस फिल्म होगी। 'मिशन मंगल' फिल्मकार आर. बाल्की के सहयोग से बन रही है, जिसका डायरेक्शन जगन शक्ति करेंगे। फिल्म की शूटिंग नवम्बर के मध्य से शुरू होगी। अक्षय ने बातचीत में कहा, 'मैं फॉक्स स्टार स्टूडियोज के रूप में नया क्रिएटिव साझेदार पाकर खुश हूं और इस सहयोग के लिए उत्सुक हूं, जो एक सार्थक और मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगा।' उन्होंने कहा कि हमारी ऊर्जा के साथ हम केवल ऐसी फिल्में तैयार करने की उम्मीद करते हैं जो न केवल उत्सुकता पैदा करे बल्कि सशक्त भी बनाए।

मैंने कभी सलमान और शाहरुख से प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं की

बॉलीवुड के तीनों खानों के बीच काफी बेहतर आपसी समझ और संबंध हैं। तीनों एक–दूसरे की अहमियत को अच्छे से समझते हैं। जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने आगामी फिल्म 'जीरो' की पटकथा सुनने के बाद शाहरुख खान का नाम सुझाया था, वहीं आमिर खान ने भी राकेश शर्मा की बायोपिक के लिए शाहरुख को फिल्म में लेने का सुझाव दिया था। इस फिल्म की शूटिंग शाहरुख अगले साल से शुरू करेंगे। आमिर के मुताबिक, ऐसे बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि वह अपने किसी भी सह–कलाकार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। आमिर ने कहा, मैं प्रतिस्पर्धी नही हूं और मैंने कभी सलमान और शाहरुख से प्रतिस्पर्धा महसूस नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने राकेश शर्मा की बायोपिक के लिए शाहरुख का नाम इसलिए सुझाया, क्योंकि उन्हें सचमुच लगता है कि फिल्म के लिए वह एकदम फिट हैं। उन्होंने कहा, हां, मैंने स्क्रिप्ट (राकेश शर्मा बायोपिक) के बारे में सुना और मुझे यह बहुत पसंद आई। यह सच है कि मैंने शाहरुख को फोन किया और कहा कि उन्हें कहानी सुननी चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्हें भी यह पसंद आई और आखिरदार उन्होंने इसके लिए हां कह दी। दो वर्ष बाद एक बार फिर 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' के साथ दर्शकों के बीच आने को तैयार 'दंगल' के अभिनेता ने कहा, मैं उन्हें एक स्टार के रूप में देखता हूं, मैं कोई स्टार नहीं हूं। वह सुंदर, आकर्षक, बेहतरीन हैं। मैं अपने घर गया और उन्होंने मुझे अपनी अलमारी दिखाई। मुझे लगता है कि उनकी अलमारी मेरे पूरे घर जितनी बड़ी है।

फ्रेडी का किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण था

अमेरिकी अभिनेता रामी मालेक का कहना है कि फिल्म 'बोहिमियन रैप्सडी' में फ्रेडी मर्करी की भूमिका निभाना काफी चुनौतीपूर्ण था और एक संगीतकार के किरदार में खुद को ढालना उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा।' बोहिमियन रैप्सडी' क्वीन नाम के बैंड के सदस्य फ्रेडी मर्करी की बायोपिक है ।मालेक ने 'पीटीआई भाषा' से फोन पर एक साक्षात्कार में कहा, फ्रेडी का किरदार निभाना मुश्किल था। उनकी कहानी बयां करने लायक है। जब भी आप फ्रेडी के बारे में सोचते हैं तो एक अलौकिक मनुष्य की कल्पना करते हैं। जो कुछ एक व्यक्ति के लिए असंभव माना जाता है उसे उन्होंने कर दिखाया। 'फॉक्स स्टूडियो' फिल्म 'बोहिमियन रैप्सडी' को 16 नवंबर को भारत में रिलीज करेगा।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह